हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

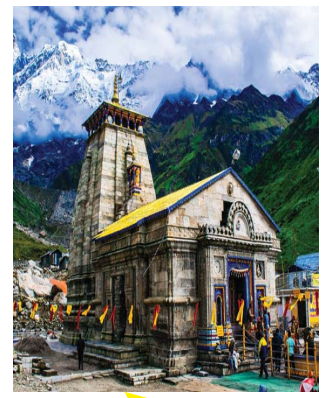

वर्ष:5 अंक:30 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये

pathpravah.com

हरिद्वार, बुधवार, 04 फरवरी 2026

उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया कीर्तिमान, इस साल आकंड़ा 6 करोड़ के पार

हरिद्वार पहुंचे सर्वाधिक 3 करोड़ 42 लाख 49 हजार पर्यटक और तीर्थयात्री

पथ प्रवाह, देहरादून।

पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। बीते साल में प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने नया कीर्तिमान बनाया है। वर्ष 2025 में छह करोड़ तीन लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखण्ड आए हैं, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हरिद्वार में सबसे अधिक तीन करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक/तीर्थयात्री पहुंचे हैं। जबकि देहरादून में 67 लाख 35 हजार 71 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29 हजार 759 सैलानी आए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में पर्यटन को नई गति मिली है। पर्यटन विकास के लिए जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं पर्यटन/तीर्थ स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है। पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। धामी सरकार के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में कुल 06 करोड़ 03 लाख 21 हजार 194 पर्यटक/तीर्थयात्री उत्तराखण्ड आए हैं। इनमें एक लाख 92 हजार 533 विदेशी सैलानी शामिल हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों/तीर्थयात्रियों की संख्या छह करोड़ के पार पहुंची है। पूर्व के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2021 में 2,00,18,115, 2022 में 5,39,81,338, 2023 में 5,96,36,601 और वर्ष 2024 में 5,95,50,277 पर्यटक/तीर्थयात्रियों ने उत्तराखण्ड का रुख किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। हमारी सरकार राज्य में पूरे वर्ष पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासियों और युवाओं को सालभर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। शीतकालीन यात्रा इसी की एक कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां गंगा जी के दर्शन को उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा की यात्रा पर आने के बाद राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखण्ड पहुंचे हैं। हमने पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने के साथ उनकी सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की बढ़ती संख्या हर वर्ष नया रिकॉर्ड बना रही है।

पर्वतारोहण: उत्तराखंड में 83 प्रमुख हिमालयी चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खुलीं

पथ प्रवाह, देहरादून।

देवभूमि उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने वन विभाग के समन्वय से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।

उत्तराखंड में खोली गई चोटियों की ऊंचाई 5,700 मीटर से 7,756 मीटर तक है, जिनमें कामेट (7,756 मीटर), नंदा देवी ईस्ट, चौखंबा समूह, त्रिशूल समूह, शिवलिंग, सतोपंथ, चंगाबांग, पंचचूली और नीलकंठ जैसी विश्व प्रसिद्ध और चुनौतीपूर्ण चोटियां शामिल हैं। ये शिखर न केवल तकनीकी कठिनाई और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि हिमालय की भव्यता के जीवंत प्रतीक भी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी शक्ति है। प्रदेश की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलना राज्य के साहसिक पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हमारा उद्देश्य है कि देश के युवा पर्वतारोहण जैसे साहसिक क्षेत्रों में आगे

आएं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित हो। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सीमावर्ती व दूर-दराज क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने देश-विदेश के सभी पर्वतारोहियों का इन अद्भुत हिमालयी शिखरों पर स्वागत करते हुए कहा है कि यह पहल देवभूमि उत्तराखंड की साहसिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मील का पत्थर साबित होगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 में पहाड़ी राज्यों के पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाली महत्वपूर्ण घोषणा की है। बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का ऐलान किया गया है। यह कदम भारत को विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग गंतव्य बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है, जो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करेगा।

भारतीय पर्वतारोहियों को बड़ी राहत

अधिसूचित 83 चोटियों पर अब भारतीय पर्वतारोहियों को कोई अभियान शुल्क (पीक फीस, कैंपिंग फीस, पर्यावरण शुल्क आदि) नहीं देना होगा। पहले यह शुल्क भारतीय पर्वतारोहण संस्था (द्धख्र) और वन विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार स्वयं इसका वहन करेगी। इससे आर्थिक बाधाओं के कारण पीछे रह जाने वाले युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा।

विदेशी पर्वतारोहियों के लिए सरल व्यवस्था

विदेशी पर्वतारोहियों पर पहले लगने वाले राज्य स्तरीय अतिरिक्त शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें केवल द्धख्र द्वारा निर्धारित शुल्क ही देना होगा। इससे उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपील बढ़ेगी और विदेशी अभियानों की संख्या में इजाफा होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

सभी पर्वतारोहण अभियानों के लिए आवेदन अब उत्तराखंड माउंटेनियरिंग परमिशन सिस्टम (चख्क्च) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। यह प्रणाली पारदर्शी, तेज और पूरी तरह डिजिटल है, जिससे अनुमति प्रक्रिया में देरी नहीं होगी।

स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

इस फैसले से सीमावर्ती गांवों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। स्थानीय लोगों को गाइड, पोर्टर, होमस्टे, परिवहन और अन्य सेवाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह पहल पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर सख्ती

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अभियानों में सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। पर्वतारोहियों को 'लीव नो ट्रेस' सिद्धांत अपनाना होगा और हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

सिन्द्रवाणी गांव से 5 वर्षीय बच्चा उठा ले गया गुलदार, प्रशासन हाई अलर्ट पर

पथ प्रवाह, रुद्रप्रयाग

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में गुलदार के हमले की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया है। सिन्द्रवाणी गांव में गुलदार द्वारा पांच साल के मासूम बच्चे को उठा ले जाने की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया और वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन व डीडीआरएफ की संयुक्त टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन स्वयं पूरे सर्च ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके निर्देश पर छह अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जिनमें वन विभाग के 20 कर्मी, डीडीआरएफ के 9 जवान और जिला प्रशासन के 5 अधिकारी शामिल हैं। घटनास्थल पर एसडीएम रुद्रप्रयाग, एसडीओ वन विभाग, डीडीएमओ और जिला सूचना अधिकारी मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल के आसपास बच्चे के कपड़े बरामद किए गए हैं, जबकि कई स्थानों पर पत्थरों पर खून के कतरों के निशान भी मिले हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। ग्रामीण भी अपने स्तर पर जंगल और आसपास के इलाकों में ढूंढ-खोज में जुटे हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से घरों में रहने, बच्चों पर विशेष निगरानी रखने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। फिलहाल गुलदार की तलाश लगातार जारी है और पूरे इलाके में भय व सन्नाटा पसरा हुआ है।

गंगा के तेज बहाव में फंसे युवक के लिए देवदूत बनी पुलिस, सूझबूझ और सीपीआर से बचाई जान

पथ प्रवाह, ऋषिकेश।

त्रिवेणी घाट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बह रहे एक युवक को पुलिस और आपदा राहत दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाल लिया। युवक की हालत नाजुक होने पर मौके पर ही सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई। पुलिस की इस मानवीय और साहसिक कार्रवाई की घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने जमकर सराहना की। जानकारी के अनुसार, दिनांक 03 फरवरी 2026 को त्रिवेणी घाट पर प्रांजल (उम्र लगभग 35 वर्ष), निवासी भनियावाला, देहरादून गंगाजी में स्नान कर रहा था। इसी दौरान गंगा के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से वह बहकर डूबने

लगा। घाट पर मौजूद लोगों ने जब युवक को डूबते देखा तो तत्काल इसकी सूचना वहां तैनात पुलिस कर्मियों को दी। सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी, जल पुलिस एवं आपदा राहत दल के जवानों ने आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आपदा राहत उपकरणों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को 72 सीढ़ी के पास गंगा के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। बहाव में काफी दूर तक बह जाने के कारण युवक की सांस और धड़कन बेहद धीमी हो चुकी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बचाव दल ने पूरी सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए एंबुलेंस के पहुंचने तक मौके पर ही युवक को सीपीआर दिया। अथक प्रयासों के बाद युवक को होश में लाया गया और तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन में आपदा राहत दल 40वीं बटालियन हरिद्वार के कांस्टेबल हरीश कुमार, संतराम और अनिल कुमार, जल पुलिस के गोताखोर विनोद सेमवाल तथा त्रिवेणी घाट चौकी के कांस्टेबल भुवन चन्द्र की अहम भूमिका रही।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया परिवहन कार्यालय का निरीक्षण, ई रिक्शा चालकों से किया संवाद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अचानक मंगलवार को परिवहन कार्यालय पहुंच गए। यहां उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के लिए चलाये जा रहे सत्यापन अभियान की समीक्षा कर चालकों से बातचीत भी की। इस दौरान कार्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने ई-रिक्शा चालकों को सत्यापन अभियान के उद्देश्य से अवगत कराते हुए ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित संचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि केवल सत्यापित चालक एवं सत्यापित ई-रिक्शा ही सड़कों पर संचालित हों,

जिससे अवैध एवं अनियंत्रित संचालन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए है कि बिना सत्यापन के किसी भी ई रिक्शा का संचालन ना किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित ई-रिक्शाओं पर रूट-वाइज रंग-कोडित क्यूआर स्टिकर स्वयं चस्पा किए गए। यह क्यूआर स्टिकर पुलिस द्वारा चालक/मालिक सत्यापन तथा आरआई द्वारा वाहन सत्यापन के उपरांत ही जारी किए जा रहे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित ई-रिक्शा का संपूर्ण सत्यापन विवरण प्रदर्शित होता है। यह अभियान जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत एसओपी के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ई-रिक्शा संचालन में पारदर्शिता, अनुशासन एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिलाधिकारी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जनहित एवं सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया तथा अभियान को निरंतर प्रभावी रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कार्यालय परिसर में उपस्थित ई-रिक्शा चालकों से भी संवाद करते हुए चलाये जा रहे सत्यापन अभियान के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा सहित सभी कार्मिक उपस्थित भी उपस्थित रहे।

सख्तीः सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से पोस्टर चिपका कर बदरंग करने वालों पर मुकदमा

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हुए सख्त, कनखल थाने में 9 के खिलाफ दर्ज हुआ केस

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद में सरकारी सम्पति को भद्दा एवं विरुपित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज कराए जा रहे हैं। सभी उप जिलाधिकारियो एवं संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनकी संपत्ति पर यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी प्रचार प्रसार करता है एवं सरकारी संपत्ति को विरुपित करता है तो उनके विरुद्ध विरूपण अधिनियम के तहत नियम अनुसार अवश्यक कार्रवाई की जाए।

उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संरचना एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने दीवारों पर अवैध लिखावट, पोस्टर चिपकाकर सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने का कार्य किया गया है। जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत थाना कनखल में 09 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

उन्होंने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 334, मुजफ्फरनगर-हरिद्वार भाग के 4 लेन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्तमान में प्रचालन एवं रखरखाव चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के किमी 198 से किमी 200 हरिद्वार की ओर के मध्य कुछ व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर स्थित सड़क संरचना एवं दीवारों पर बार-बार अपना प्रचार विज्ञापन लिखवाया जा रहा है। यह कृत्य न केवल सार्वजनिक एवं राजमार्ग संरचना को क्षति पहुंचाने वाला है, बल्कि संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय भी प्रतीत होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग रख रखाव टीम द्वारा पूर्व में इन लिखावटों को पेंट कर मिटाया गया था कुछ संस्थानों एवं व्यक्तियों द्वारा पुनः यही अवैध लिखावट कर दी गई है।

इसकी जानकारी जिलाधिकारी को दी गई, जिसका जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने अवगत कराया कि जिसके विरुद्ध अवैध लिखावट एवं दीवारों, सड़क संरचना की बदसूरती के कारण शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इस प्रकार के भद्दे एवं अत्यधिक प्रचार से वाहन चालकों का ध्यान भी भटकता है, जिससे राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक सपत्ति को क्षति पहुँचाने एवं राजमार्ग की सुरक्षा से खिलवाड करने संबंधी प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत थाना कनखल में 09 लोगों/संस्थानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने ने यह भी अवगत कराया है कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 में सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित करने पर एक वर्ष की सजा तथा ?10000 तक के जुर्माने का प्राविधान है।

एक नजर

नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 23 नशीले इन्जेक्शन हुए बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान'' के तहत इस मिशन को सफल करने के ?लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बहादराबाद पुलिस ने एक नशा तस्कर को प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष बहादराबाद के नेतृत्व में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान नहर पटरी रानीपुर झाल के पास बहादराबाद से आरोपी गौरव पुत्र अमर सिंह निवासी- ग्राम शेखपुरा कुमारगढ थाना कनखल जिला हरिद्वार को 23 नशीले इन्जेक्शन के साथ पकडा। पूछताछ में आरोपी द्वारा बडे ड्रग्स पैडलरों के नामों का खुलासा किया गया है। प्रकाश में आये ड्रग्स पैडलरों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटककर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के अनुसार, मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि जोगिया मंडी में एक युवक ने अपने कमरे के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान कन्हैया (30) पुत्र पप्पू गिरी निवासी जोगिया मंडी नगर कोतवाली के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो कन्हैया फंदे पर लटका हुआ था।शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह का कहना है कि कन्हैया कांगड़ा घाट पर फूल बेचता था। वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इसके पीछे बीमारी भी वजह बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

कोटद्वार जा रहे भीम आर्मी के सदस्यों को पुलिस ने हरिद्वार में रोका

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोटद्वार में चल रहे विवाद के बीच दीपक कुमार के समर्थन में जा रहे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और उनके समर्थकों को पुलिस ने हरिद्वार में ही चंडीघाट चौकी पर रोक दिया। कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर अड़े रहे लेकिन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। जिससे मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया।

बातचीत विफल होने के बाद पुलिस ने महक सिंह सहित कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रोशनाबाद भेज दिया। जानकारी के मुताबिक, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह अपने समर्थकों के साथ कोटद्वार रवाना हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही चंडीघाट चौकी पर घेराबंदी की गई। हालात संभालने के लिए सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी, शहर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई।

स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतते हुए महक सिंह और उनके कुछ समर्थकों को पुलिस वाहन में बैठाकर रोशनाबाद ले जाया।

चंडीघाट पर रोके जाने के बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। महक सिंह का आरोप था कि दीपक कुमार को समर्थन देना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का काम कर रही है।

हरिद्वार पुलिस का पशु क्रूरता करने वालों पर शिकंजा, दो आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल द्वारा गौकशी व अवैध पशुओं के कटान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं। इसी क्रम में कोतवाली सिविल लाइन, रुड़की पुलिस टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी कि मच्छी मोहल्ले में सरकारी कुएं के पास जमशेद के घेर में उमर गुल पुत्र फुरकान निवासी मच्छी मौहला कोतवाली रुड़की और अफजल पुत्र सगीर निवासी रामपुर कोतवाली गंगनहर के द्वारा भैंस का अवैध काटन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा

छापेमारी की कार्यवाही करते हुये उमर गुल और अफजल को जमशेद का घेर निकट सरकारी कुआं मच्छी मौहला रुड़की से पकड़ा। आरोपितों के कब्जे से 120 किलो भैंस वंशीय मांस व पशु कटान उपकरणों को बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली रुड़की पर पशु क्रूरता निवारण अधि0 बनाम उमर गुल आदि पंजीकृत किया गया है ।

विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर तैयार किया गया संपूर्णता अभियान 2.0-आदेश चौहान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

संपूर्णता अभियान 2.0 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास भवन रोशनाबाद के प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका मुख्य आथिति विधयाक रानीपुर आदेश चौहान, शिवालिक नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

यह अभियान 2.0 बीती 28 जनवरी से शुरू हो गया है जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 5 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सैचुरेशन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाना है। इन 3 महीने के अभियान के तहत आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में

महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों को पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाएगा।

आकांक्षी जिला हरिद्वार तथा आकांक्षी ब्लाक बहादराबाद में संपूर्णता अभियान 2.0 के 6 संकेतांको को संतृप्त करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाले 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिशत।, रिपोर्टिंग माह के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों की माप दक्षता।, कार्यात्मक शौचालय वाले संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत, पेयजल सुविधा वाले संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रतिशत।, स्कूलों की कुल संख्या के सापेक्ष लड़कियों के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत, टीकाकृत गोवंश (एफएमडी का टीकाकरण) का प्रतिशत।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रानीपुर आदेश चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जो संकल्प ओर विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है वह आज पूरे देश का संकल्प बना हुआ है उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया है जिसके अंतर्गत पूरे देश में 112 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमें कुछ पैरामीटर तय किए गए है जिसके आधार पर स्वस्थ्य, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र से सम्बंधित विस्तृत कार्य किया जाना है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत हमें 90 दिनों में कुछ पैरामीटर तय किये गए है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य कृषि से संबंधित हैं इसके लिए आज यहां इस अभियान की शुरुआत की गई है जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर जो भी पैरामीटर के अनुसार रणनीति तैयार की जाएगी उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित पैरामीटर निर्धारित समय अवधि की अंतर्गत पूरा करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष शिवालिक नगर राजीव शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी आरके सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ललिनी ध्यानी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम बाल विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

एक नजर

होटल में ठहरी एनआरआई महिला की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। धर्मनगरी की नगर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल में ठहरी एनआरआई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। मृतका की पहचान 66 वर्षीय अन्ना चौहान के रूप में हुई है। वह यूके से 17 सदस्यीय दल के साथ भारत घूमने के लिए आई थी। जानकारी के मुताबिक एक दिन पूर्व हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र स्थित शांति हेरिटेज होटल में एक महिला आकर ठहरी थी। महिला ने अपना नाम अन्ना चौहान बताया। उसके साथ उसके साथी भी होटल में ठहरे थे। मंगलवार सुबह होटल के कर्मचारियों ने कमरे के अंदर से कोई हलचल होती न देख दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर दरवाजा खोला गया, जहां अंदर महिला बैड पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव कब्जे में लिया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि महिला की हार्ट अटैक से मौत हुई है। मामला यूके से जुड़ा हुआ होने के कारण पुलिस प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक महिला कई लोगों के एक दल में शामिल होकर इंग्लैंड से भारत घूमने आई थी।

लक्सर लूटकांड में पुराना नौकर निकला मास्टरमाइंड, तीन आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण में सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रही है। इसी क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से हुई लूट की वारदात का बेहद कम समय में खुलासा करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,85,000/- नकद, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पीड़ित का आधार कार्ड व बैग भी बरामद किया है। घटना 01 फरवरी 2026 की है, जब वादी रवि राठौर पुत्र मुन्ना लाल, निवासी लक्सर ने कोतवाली लक्सर में तहरीर दी कि चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट की और कलैक्शन के पैसों से भरा बैग व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली लक्सर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी हरिद्वार द्वारा प्रकरण के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से सुरागरसी और पतारसी शुरू की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास संदिग्ध गतिविधियों, मोटरसाइकिल के उपयोग और स्थानीय इनपुट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। 02 फरवरी 2026 को चेकिंग के दौरान लक्सर क्षेत्र से तीन संदिग्धों को दबोचा गया, जिनका हुलिया वारदात में शामिल आरोपियों से मेल खाता था। पूछताछ में मुख्य आरोपी गुलशेर ने खुलासा किया कि वह पहले लक्सर की एक परचून की दुकान पर काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसने बदले और लालच की भावना में अपने साथियों सलमान, फरमान और साहिल के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। उसे जानकारी थी कि रवि हर रविवार दुकानों से मोटी रकम का कलेक्शन करता है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर चारों ने डंडों से मारपीट कर बैग लूट लिया।

गिरफ्तार आरोपीः 1- गुलशेर पुत्र कामिल निवासी खण्डजा कुतुबपुर, कोतवाली लक्सर
2- फरमान पुत्र वसीम निवासी खण्डजा कुतुबपुर, कोतवाली लक्सर
3- साहिल पुत्र नफीस निवासी खण्डजा कुतुबपुर, कोतवाली लक्सर
कुल बरामदगी

1,85,000/- नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, वादी का आधार कार्ड, काले रंग का बैग।

पुलिस टीमः व0उ0नि0 लोकपाल परमार, उ0नि0 नरेन्द्र सिंह, अ0उ0नि0 रंजीत नौटियाल, हे0का0 विनोद कुमार, हे0कानि0 मनोज मिनान, कानि0 अनुप पोखरियाल, कानि0 संदीप रावत, कानि0 किशोर नेगी।

शारदीय कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार पुलिस ने जारी किया यातायात डायवर्जन प्लान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

शारदीय कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान जारी किया है। इस यातायात रूट डायवर्जन प्लान के तहत 5 फरवरी से हरिद्वार–नजीबाबाद मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

शारदीय कांवड मेले के दौरान डायवर्जन प्लान 5 फरवरी की सुबह 8 बजे से लागू किया जाएगा जो 15 फरवरी को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। देहरादून, ऋषिकेश की ओर से नजीबाबाद मार्ग पर जाने वाले भारी वाहनों को हरिद्वार से रूड़की होते हुए वाया मुज्जफरनगर भेजा जाएगा। वापसी भी इसी रूट से होगी। हरिद्वार जनपद से नजीबाबाद, मुरादाबाद, नैनीताल की तरफ जाने वाले आवश्यक सामग्री (खाद्य सामग्री, पैट्रोलियम, गैस,मेडिकल) के वाहनों का आवागमन रात में

11 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगा। बिजनौर, मुरादाबाद, नैनीताल जाने वाली रोड़वेज बसें लाडपुर से नहर पटरी होते हुए भेजी जाएंगी। वापसी में बसों को बिजनौर से मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार लाया जाएगा। कोटद्वार से हरिद्वार आने वाली प्राईवेट बसों का मार्ग यथावत रहेगा। रूड़की से लक्सर होते हुए बालावाली मार्ग पर भारी और मध्यम वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। जरूरत पड़ने पर हल्के वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि मेला पर्व पर शहर में नजीबाबाद की ओर से आने वाले छोटे निजी वाहनों को 4.2 डायवर्जन प्वाईंट से चंडीचौक लाया जाएगा। इसी तरह दिल्ली हाइवे की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहनों को शंकराचार्य चौक तक लाया जाएगा। यातायात का अत्यधिक दबाव बढ़ने पर इधर से आने वाले वाहनों को नगला इमरती अंडर पास से डायवर्ट कर वाया लक्सर हरिद्वार लाया जाएगा। चीला मार्ग केवल ऋषिकेश से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए प्रयोग होगा, जिसमें वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी। चीला-टी प्वांईट व भीमगौड़ा बैराज से बैरियर लगाकर वन-वे किया जाएगा।

बापू ग्राम भूमि मामले पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन मंत्री से की मुलाकात

पथ प्रवाह, नई दिल्ली

पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान ऋषिकेश से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के साथ बापू ग्राम क्षेत्र से संबंधित भूमि विवाद एवं स्थानीय जनता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की गई। बैठक में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बापू ग्राम क्षेत्र की जमीनी हकीकत से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि यह मामला केवल भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां निवासरत नागरिकों के अधिकारों, आजीविका और भविष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय का व्यावहारिक, न्यायसंगत और शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि लंबे समय से असमंजस में रह रहे लोगों को राहत मिल सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बापू ग्राम से जुड़े मुद्दे की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से विचाराधीन लेने का भरोसा दिलाया। उन्होंने यथासंभव सहयोग और समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि

संबंधित पहलुओं पर तथ्यों और नियमों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधिमंडल में रमेश जुगलान (संयोजक, बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति), संदीप गुप्ता (पूर्व राज्यमंत्री), रविंद्र राणा (पूर्व जिलाध्यक्ष, भाजपा ऋषिकेश), ज्योति सिंह सजवान (पूर्व जिलाध्यक्ष, भाजपा परवादून), राजेंद्र बिष्ट (पार्षद नगर निगम ऋषिकेश एवं सांसद प्रतिनिधि), रामकुमार कश्यप (समाजसेवी एवं व्यापारी नेता) तथा बिजेंद्र रमोला (पार्षद नगर निगम ऋषिकेश) शामिल रहे।

इंस्पायर अवार्ड में आदित्य की उड़ान, राज्य स्तर पर जनपद का नाम रोशन

पथ प्रवाह, गोचर।

जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता (DLPC) का आयोजन 2 फरवरी 2026 को पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोचर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विकासखंड पोखरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विरसण के छात्र आदित्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया। आदित्य ने सीमेंट कार्य में लगे मिस्त्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव और व्यावहारिक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उनका प्रोजेक्ट फोल्डेबल व एडजेस्टेबल ट्रूल कर्नी (मजिला) पर आधारित है, जिसे हाथ के हैंडल से आसानी से चौड़ा व संकरा किया जा सकता है। इस ट्रूल की खासियत यह है कि यह संकरी जगहों में भी बड़ी कर्नी की तरह फिनिशिंग का कार्य सरलता से कर सकती है, जिससे श्रमिकों का समय, श्रम और संसाधन तीनों की बचत होगी। आदित्य के मार्गदर्शक शिक्षक संदीप नेगी ने छात्र की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि

यह प्रोजेक्ट भविष्य में समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य गजेंद्र रावत, एसएमसी अध्यक्ष जयदीप बुटोला, ग्राम प्रधान शंकर सिंह नेगी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य ईश्वर नेगी ने आदित्य को बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और हर्ष का विषय बताया। आदित्य की इस सफलता ने न केवल विद्यालय बल्कि पूरे पोखरी विकासखंड का नाम रोशन किया है।

संपादकीय

मदरसा बोर्ड से प्राधिकरण तक

उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव करते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। जुलाई 2026 से लागू होने जा रहे इस फैसले को सरकार शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं इसके निहितार्थ सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहराई से चर्चा का विषय बन गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में ही मदरसा बोर्ड को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था से बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाते। नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी और पाठ्यक्रम निर्धारण का अधिकार नवगठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के पास होगा। इससे एक समान शैक्षिक ढांचा विकसित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्राधिकरण के गठन में सरकार ने विविध समुदायों के शिक्षाविदों को शामिल करने का प्रयास किया है। डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विभिन्न समुदायों से जुड़े प्रोफेसर, शिक्षाविद, समाजसेवी और प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। यह संरचना संकेत देती है कि सरकार इसे केवल किसी एक समुदाय तक सीमित न रखकर व्यापक अल्पसंख्यक शिक्षा मंच के रूप में विकसित करना चाहती है।

हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह बदलाव वास्तव में शैक्षिक सुधार तक सीमित रहेगा या इसकी छाया सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वायत्तता पर भी पड़ेगी। मदरसा व्यवस्था केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा भी रही है। ऐसे में बिना व्यापक संवाद और विश्वास निर्माण के यह फैसला कुछ वर्गों में असहजता पैदा कर सकता है।

सरकार का दावा है कि नया प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को आधुनिक, रोजगारोन्मुख और प्रतिस्पर्धी शिक्षा मिले, जिससे वे राष्ट्रीय मुख्यधारा में मजबूती से खड़े हो सकें। यदि यह उद्देश्य ईमानदारी से लागू होता है और पाठ्यक्रम निर्धारण में संतुलन, समावेशन और संवेदनशीलता बरती जाती है, तो यह कदम भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

मदरसा बोर्ड से प्राधिकरण तक का यह बदलाव उत्तराखंड की शिक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ है। अब असली परीक्षा नीति के क्रियान्वयन की होगी–जहां शिक्षा सुधार, सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों के बीच सही सामंजस्य ही इस फैसले की सफलता तय करेगी।

छात्रों को हिंदी विज्ञान में कार्य करने के लिए वैज्ञानिक

संजय गोस्वामी

आज छात्रों को हिंदी विज्ञान में कार्य करने के लिए वैज्ञानिक कार्यों का करना राजभाषा के लिए शुभ है विज्ञान संचार को हम यूं समझ सकते है, जैसे कि वैज्ञानिक जानकारियों जहां से पैदा हो रही हैं। वहां से लेकर उन जानकारियों के प्रयोग करने वालों तक पहुंचाना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम अपनाए जाते हैं। विज्ञान संचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शोधपरक विज्ञान संचार और दूसरा लोकप्रिय विज्ञान संचार। लैब में होने वाले शोधों की जानकारी तकनीकी भाषा में होती है। इसे आम आदमी सुगमता से नहीं समझ सकता। लोकप्रिय विज्ञान संचार में यह परेशानी आती है कि विज्ञान की कठिन बातों को सरल कैसे बनाया जाए और आम लोगों तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिसर्च पेपर की भाषा को आम लोग समझ नहीं पाते और वैज्ञानिक आम जन की भाषा को नहीं समझ पाते। यहीं पर परेशानियां पैदा होती हैं। वास्तव में विज्ञान के जटिल तर्कों को सरल भाषा में जो भी आम लोगों तक पहुंचा देगा वही एक सफल विज्ञान संचारक कहलाएगा। वास्तव में विज्ञान संचार के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी आम जन तक पहुंचाना और उनमें वैज्ञानिक-तकनीकी दृष्टिकोण का विकास करना। किसी भी व्यक्ति में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होने की बात की जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि उसमें सोच, आचरण, व्यवहार और निर्णय लेने के स्तरों पर वैज्ञानिकता की छाप अवश्य दिखे।इसी छाप को अखिल भारतीय स्तर पर बनाये रखने के लिए हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, मुंबई द्वारा पिछले 57 वर्ष से लगातार विज्ञान संचार किया जा रहा जिसमें किसी परिषद के पूर्व निष्ठावान विद्वान द्वारा हिंदी विज्ञान में एक नई क्रांति मुंबई के वैज्ञानिकों ने 1968 में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की नींव मुंबई में रखी और 2साल बाद वैज्ञानिक पत्रिका का सतत प्रकाशन हुआ जो आज भी ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। अतः राष्ट्रीय अस्तर पर हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद ही एक मात्र ऐसी संस्था बची जो विज्ञान संचार हेतु 1 वर्ष में 4 अंक का नियमित प्रकाशन कर रही है जिसके वर्तमान संपादक श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा हैं एक अनाधिकृत संस्थान भी वैज्ञानिक का डुप्लीकेट कॉपी निकाल रही है जो पोथी पर ऑनलाइन विक्रय किया जा रहा वह नकली है बता दें वैज्ञानिक पत्रिका हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद के आजीवन सदस्यों को मुफ्त में दिया जाता है और विज्ञान को हिंदी में प्रसार हेतु यह अंक पूर्णतः निशुल्क है.वैज्ञानिक का अगला अंक जनवरी -मार्च 26 सांख्यिकीय विशेष अंक होगा अतः विज्ञान व गणित के छात्रों से अनुरोध है कि कृप्या10दिनों के अंदर परिषद के ईमेल पर अपना आलेख व परिचय के साथ समय के अंदर आलेख भेज सकते हैं.इनोवेशन के लिए साइंस कम्युनिकेशन या विज्ञान संचार सबसे ज़रूरी है आज देश को विज्ञान की सही जानकारी हेतु विज्ञान संचार बहुत जरुरी है, यदि आप बेरोजगार हैं, तो इन वास्तविकताओं का सामना करने से आप अक्सर अभिभूत, उदास और निराश महसूस कर सकते हैं। वैश्विक महामारी के लिए ये वैध प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन साइंस कम्युनिकेशन सकारात्मक बने रहें इसके लिए वैज्ञानिक लेखन को गतिशील बनाने की जरुरत है ताकि हमारे भारत में हिंदी में विज्ञान का कर सकें.वैज्ञानिक (त्रैमासिक) - प्रतियोगिता विशेषांक में में विशेष-विषय जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में डेंगू, थैलेसीमिया पशु में कैंसर, ई खेती, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, कल्पना चावला की जीवनी आदि लेख वैज्ञानिक ज्ञान से भरा , समसामयिक और रोचक रहा है , 'वैज्ञानिक' के संपादन एवं व्यवस्थापन से जुड़े सभी विज्ञान प्रेमियों द्वारा लेखन जगत की परिवृद्धि के लिए ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। हिन्दी विज्ञान की लोकप्रिय पत्रिका वैज्ञानिक से जुड़े सभी विज्ञान लेखकों पाठकों और सृजनशील व्यक्तियों के निरंतर सहयोग, स्नेह, विश्वास और वैज्ञानिक से लगाव है।

विकसित भारत बनाने में भारतीय रेल परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार

विनोद कुमार सिंह

मोदी सरकार के आम बजट मे मिशन और केन्द्रीय रेल अश्विनी वैष्णव का ऐतिहासिक विजन में भारतीय रेल देश की आर्थिक रीढ़ व विकसित भारत बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा

वैश्विक मानचित्र पर आए दिनों चर्चा व चिन्तन भारत का होना आम बात है, लेकिन इन दिनों आम बजट मे रेल मंत्रालय को आवांटित राशि को ले चहूँ दिशाओं में विकाश की तेज रफ्तार व सीटी सुनाई पड़ने लगी है। केन्द्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है और यह बजट केवल सरकार के आय-व्यय का लेखा नहीं,बल्कि भारत के भविष्य का वह निर्णायक दस्तावेज है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को नई शक्ति देता है। इस बजट का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि भारतीय रेल को केन्द्र में रखकर मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण की गति को और तेज करने का स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'विकसित भारत मिशन' और केन्द्रीय रेलमंत्रीअश्विनी वैष्णव का आधुनिक रेलवे विजन अब कागजों की योजना नहीं,बल्कि बजट की ठोस घोषणाओं और रिकॉर्ड निवेश के माध्यम से यथार्थ की धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। भारतीय रेल आज अपने यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाने वाली व्यवस्था नहीं रह गई, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़,उद्योगों की जीवनरेखा,कृषि बाजारों की शक्ति और रोजगार सृजन का सबसे बड़ा इंजन बन चुकी है। आप को मै स्पष्ट कर दुँ किवर्ष 26- बजट में भारतीय रेल को लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है,जो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार माना गया है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निवेश को देश की आर्थिक पटरी पर तेज रफ्तार विकास का विजय घोष कहा है। सर्वविदित रहे कि पिछले दशक में रेलवे में जिस स्तर पर परिवर्तन आया है,वह स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। रेलवे नेटवर्क का विस्तार,नई तकनीक का समावेश,स्टेशन पुनर्विकास,हाई- स्पीड रेल परियोजनाएँ और हरित ऊर्जा की दिशा में कदम- यह सब भारत को एक नई रेल क्रांति की ओर ले जा रहा है। रेल बजट 2026-27 का सबसे बड़ा आकर्षण सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा है। ये कॉरिडोर भारत के औद्योगिक केन्द्रों,व्यापारिक शहरों, कृषि उत्पादन क्षेत्रों और निर्यात हब को तेज गति से जोड़ेंगे। हाई-स्पीड रेल नेटवर्क केवल यात्रियों के समय की बचत नहीं करेगा,बल्कि यह निवेश आकर्षण,उद्योग विस्तार, पर्यटन विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के तीव्र उत्थान का माध्यम बनेगा। जब शहरों के बीच दूरी घटती है,तब व्यापार की गति बढ़ती है,नए रोजगार के अवसर पैदा होते है। इससे आर्थिक गतिविधियाँ कई गुना तेज हो जाती हैं। दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी- सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर उत्तर भारत और पूर्वी भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। यह विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों का सबसे बड़ा संकेत है। इसी बजट में हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। भारत अब केवल परंपरागत डीजल इंजनों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण अनुकूल,ऊर्जा दक्ष और भविष्य की परिवहन प्रणाली का प्रतीक हैं। इससे प्रदूषण घटेगा, ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत हरित परिवहन क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाएगा। यह वही सोच है जो विकसित राष्ट्रों की पहचान बन चुकी है। अब भारत भी उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना को भी बजट 2026-27 में नई ऊर्जा मिली है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और आधुनिक राष्ट्र निर्माण की पहचान बन चुकी है। बुलेट ट्रेन केवल एक रेल सेवा नहीं,बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, निवेश सामर्थ्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार भारत को हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट के वैश्विक मानचित्र पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा।

रेलवे विद्युतीकरण भी इस बजट का एक मजबूत स्तंभ है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय रेल नेटवर्क पूर्णतः विद्युतीकृत होकर ऊर्जा दक्ष, तेज,सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बने। विद्युतीकरण से परिचालन लागत घटेगी,माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगा। रेलवे की गति केवल ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ाएगी,बल्कि यह भारत की आर्थिक गति को भी तेज करेगी। रेल बजट 2026-27 का सबसे प्रत्यक्ष और जनसरोकार से जुड़ा पक्ष अमृत भारत स्टेशन योजना है। देशभर में सैकड़ों रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशन अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक यात्री सुविधा केन्द्र,व्यापारिक गतिविधियों के हब और स्थानीय रोजगार के केन्द्र बनेंगे। छोटे शहरों और कस्बों में स्टेशन विकास से होटल,टैक्सी, दुकानें,स्थानीय हस्तशिल्प, खानपान उद्योग और पर्यटन व्यवसाय को नया जीवन मिलेगा। रेलवे स्टेशन अब विकास के प्रवेश द्वार बनेंगे। नई रेल लाइनों,डबलिंग, ट्रैक अपग्रेडेशन और फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी बजट में विशेष बल दिया गया है। माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे को आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में बदला जा रहा है। इससे कृषि उत्पाद तेजी से बाजारों तक पहुँचेंगे,उद्योगों को कच्चा माल समय पर मिलेगा और निर्यात क्षेत्र को नई शक्ति मिलेगी। रेलवे विकास का अर्थ केवल यात्री सुविधा नहीं,बल्कि भारत के उत्पादन और व्यापार की क्षमता में क्रांतिकारी वृद्धि है। इस बजट का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देगा। नई परियोजनाओं से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इंजीनियरिंग,निर्माण,तकनीकी सेवा,आईटी सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था,खानपान,पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार की व्यापक संभावनाएँ खुलेंगी। रेलवे परियोजनाएँ केवल सरकारी नौकरियाँ नहीं,बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करती हैं। राज्यवार आवंटन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि रेलवे विकास अब केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं,बल्कि पूरे भारत में संतुलित विस्तार का माध्यम बन चुका है। 2026-27 में महाराष्ट्र को लगभग 23,926 करोड़ रुपये,उत्तर प्रदेश को 20,012 करोड़ रुपये,गुजरात को 17,366 करोड़ रुपये,मध्य प्रदेश को 15,188 करोड़ रुपये,पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपये, राजस्थान को 10,228 करोड़ रुपये,बिहार को 10,379 करोड़ रुपये,झारखंड को 7530 करोड़ रुपये,ओडिशा को 10,928 करोड़ रुपये और असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को 11,486 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि रेलवे विकास नीति में क्षेत्रीय संतुलन और व्यापक विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार जैसे राज्यों में यह निवेश विशेष महत्व रखता है,क्योंकि बीते वर्षों की तुलना में बिहार को कई गुना अधिक आवंटन मिला है। इससे राज्य में नई रेल परियोजनाएँ, स्टेशन विकास,पर्यटन कनेक्टिविटी और स्थानीय व्यापार को बड़ा लाभ होगा। मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी रेलवे निवेश में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है,जो इन क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता और रोजगार अवसरों को व्यापक बनाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष आवंटन इस बात का संकेत है कि सरकार सीमांत क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रेल बजट 2026- 27 वास्तव में मोदी सरकार की उस सोच का प्रतिबिंब है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा आधार माना गया है। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत मिशन अब रेलवे जैसी जीवनरेखा में हो रहे रिकॉर्ड निवेश से वास्तविकता बनता दिख रहा है। वैष्णव का विजन भारतीय रेल को आधुनिक,सुरक्षित,तेज, पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में निर्णायक है।

कैंसर मौन महामारी, जागरूकता ही है सबसे बड़ा हथियार

योगेश कुमार गोयल

लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 4 फरवरी को 'विश्व कैंसर दिवस' मनाया जाता है। दरअसल आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर एक ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी एक महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। भारत में तो कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का बहुत देर से पता चलता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है और कैंसर से मौतों का आंकड़ा साल-दर-साल निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

हालांकि कुछ वर्ष पूर्व तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था लेकिन कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी खोजें हुई हैं और अब अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक संभव हो जाता है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का उपचार अब संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में एक बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि 'कैंसर' आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है। दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का शुरूआती चरणों में तो सफल इलाज संभव भी है। अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो हालांकि इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू एवं ग्राउंडिंग की उच्चस्तरीय समीक्षा

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत हुए एमओयू तथा उनकी ग्राउंडिंग (क्रियान्वयन) की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एमओयू की वर्तमान स्थिति, जमीनी प्रगति, अवरोधों तथा आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत कुल 3,57,693 करोड़ रुपये के 1,779 एमओयू संपादित किए गए थे, जिनमें से अब तक 1,06,953 करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के औद्योगिक एवं आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह राज्य में निवेशकों के विश्वास, बेहतर कानून-व्यवस्था, सुशासन और उद्योग अनुकूल वातावरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक परिणाम को और आगे बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, जिनका लाभ राज्यहित में लिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि एमओयू एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर आ रहे अवरोधों का त्वरित निस्तारण किया जाए। प्रत्येक संबंधित विभाग में एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो एमओयू ग्राउंडिंग की सतत मॉनिटरिंग करे।

यदि किसी नीति में संशोधन, सरलीकरण अथवा शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र पैरवी की जाए। उद्योगपतियों के साथ नियमित संवाद और संपर्क बढ़ाया जाए तथा उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटलीकरण,सरलीकृत प्रक्रियाएं और उद्योग फ्रेंडली इकोसिस्टम से संबंधित सुधारों की जानकारी दी जाए।

निर्देश दिए कि परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में अनावश्यक देरी बिल्कुल न हो, कार्यों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, स्पष्ट टाइमलाइन के अनुसार कार्य पूर्ण हों और किसी भी प्रकार की पेंडेंसी न रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ विभागों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने प्रशंसा भी की। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनय शंकर पांडेय, रणजीत सिन्हा, सी. रविशंकर, डी.एस. गर्ब्याल, वन विभाग से रंजन कुमार मिश्रा, अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यटन, उद्योग और निवेश के नए अवसरों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जिन क्षेत्रों में होटल निर्माण की व्यापक संभावनाएं हैं–जैसे पिथौरागढ़, कैंची धाम सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों–वहाँ निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग स्पेशल टूरिस्ट ज़ोन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एरिया आधारित फोकस पॉलिसी तैयार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योगों को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि राज्य के सभी जनपदों में प्रत्येक माह 'उद्योग मित्र समिति' की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें उद्योगों से जुड़े मुद्दों का समाधान तथा उद्योग-अनुकूल निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

संस्कृति, अध्यात्म और संतुलित विकास को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और प्राचीन गौरवशाली विरासत का केंद्र बिंदु है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन पर आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आवश्यक होमवर्क करने, हिंदू स्टडीज सेंटर एवं प्राच्य शोध केंद्र से संबंधित पूर्व निर्देशों पर अग्रिम कार्रवाई करने, स्पिरिचुअल ज़ोन डेवलपमेंट, भराड़ीसैंण में मंदिर एवं अन्य रचनात्मक निर्माण कार्य तथा आयुर्वेद एम्स की स्थापना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

एक नजर

कालसी में हादसा: हिमाचल रोडवेज की बस 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, 4 की मौत

पथ प्रवाह, देहरादून/कालसी। उत्तराखंड के जनपद देहरादून अंतर्गत थाना कालसी क्षेत्र में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मीनस मार्ग पर क्वानू के पास हिमाचल रोडवेज की एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिलते ही थाना कालसी पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और एसडीआरएफ की टीमों को भी राहत एवं बचाव कार्य के लिए अलर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार बस नेरवा (हिमाचल प्रदेश) से पौंटा साहिब की ओर जा रही थी, जिसमें कुल 36 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 4 लोगों–दो महिला और दो पुरुष–की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाते हुए खाई में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। पुलिस द्वारा बस सवार यात्रियों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि एक छोटे वाहन द्वारा ओवरटेक किए जाने के दौरान बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। फिलहाल दुर्घटना के सटीक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस हादसे में जिन चार लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी पहचान इस प्रकार की गई है–यासमीन बेगम (46 वर्ष), पत्नी नेक मोहम्मद, निवासी ग्राम क्यारला, नेरवा, हिमाचल प्रदेश; रिचा (30 वर्ष), पत्नी वीरेंद्र, निवासी ग्राम बिजमल, तहसील नेरवा, शिमला; धन बहादुर, पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम क्यारला, नेरवा, हिमाचल प्रदेश; तथा बस चालक दिनेश कुमार (54 वर्ष), पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम पोपाट, शिमला, हिमाचल प्रदेश। पुलिस प्रशासन द्वारा मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, वहीं घायलों के उपचार और दुर्घटना की जांच की कार्रवाई जारी है। हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी मार्गों पर यातायात सुरक्षा और ओवरटेकिंग की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए 441 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता, सीडीओ ने की बैठक

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। विकास भवन में मंगलवार को क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि (C.A. Land) के चिन्हांकन एवं समीक्षा को लेकर मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि की वर्तमान स्थिति, आवश्यकता एवं उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जनपद स्तर पर वर्तमान में 62 मोटर मार्गों के सापेक्ष लगभग 441 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि की आवश्यकता है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त वन पंचायतों का डाटा संकलन किया जा रहा है तथा तहसील स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित किया गया है। बैठक में उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारी एवं टीम सदस्यों को निर्देशित किया गया कि मोबाइल में 'नोटकैम' एप्लिकेशन डाउनलोड कर संबंधित क्षेत्रों की जियो-टैग फोटो ली जाएं। इसके उपरांत 'गूगल अर्थ' एप्लिकेशन के माध्यम से आवश्यक कोऑर्डिनेट्स पिन कर पॉलिगन तैयार किए जाएँगे एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज वन विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर जनपद स्तर पर तैनात जीआईएस विशेषज्ञ से संपर्क करने के निर्देश दिए गए।

धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन, अब प्राधिकरण तय करेगा सेलेब्स

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी।

डॉ पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है जोकि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक

पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी।इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। डॉ पराग ने बताया कि इसमें डॉ सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रो. राकेश जैन, डॉ सैय्यद अली हमीद, प्रो. पेमा तेनजिन, डॉ एल्बा मेड्रिले, प्रो. रोबिना अमन, प्रो. गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। साथ ही समाज सेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण भी सदस्य सूची में रहेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारी सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है, हमारी सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का निर्णय लिया था। अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। ये प्राधिकरण सिलेबस तय करेगा। सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोकतंत्र सेनानी पेंशन से लेकर अमृत 2.0 तक विकास को हरी झंडी

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन तथा अमृत 2.0 सहित विभिन्न विकास योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने श्रीमती देवकी काण्डपाल, पत्नी स्वर्गीय जयदत्त काण्डपाल, निवासी कुसुमखेडा, हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) को 17 मई 2023 से 20 हजार प्रतिमाह लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कई अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी। नगर निगम हरिद्वार के वार्ड संख्या 59 सीतापुर सरोवर में वाटर बॉडी रिजुविनेशन योजना हेतु 1.68 करोड़, विकासखण्ड रायपुर में बांदल नदी पर नहर के शीर्ष पर जल संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्य के लिए 2.19 करोड़ तथा बीजापुर नहर के हैड के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु ?5.00 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अंतर्गत लोहाघाट टाउन पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 84.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

शिक्षा, सुरक्षा और सड़कों पर फोकस:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा एवं आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण अनुमोदन प्रदान किए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय बालक छात्रावास, कण्डोली देहरादून में अनुरक्षण कार्य हेतु 46.56 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं, राजा बाबू पब्लिक इंटर कॉलेज, आसफग्रान्ट हरिद्वार को हाईस्कूल (कक्षा 9-10) के लिए ?2.00 लाख तथा इंटरमीडिएट (कक्षा 11-12) के लिए ?3.00 लाख, कुल ?5.00 लाख का आवर्तक/टोकन सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही हर्ष पब्लिक जूनियर हाईस्कूल, मूलदासपुर माजरा, हरिद्वार को 1.00 लाख प्रतिवर्ष प्रोत्साहन स्वरूप सहायता अनुदान देने का अनुमोदन भी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला कारागार, देहरादून में वर्तमान भूमिगत विद्युत केबल एवं पैनल को बदलकर समुचित क्षमता की आर्मर्ड केबल व पैनल स्थापित किए जाने हेतु 85.22 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जनपद पिथौरागढ़ में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत अखुली ग्राम पंचायत में संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 54.80 लाख, धारचूला विधानसभा क्षेत्र में जोशागांधी नगर से कोटाखड़िक इमला ट्रैक रूट/अश्वमार्ग (टीएसपी) के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 30.55 लाख तथा विकासखण्ड मूनाकोट के अंतर्गत ग्राम सभा घुर्चू तोक पंतरा से अखुली तोक बुर्गर तक संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 83.93 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इन निर्णयों से राज्य में विकास, शिक्षा, जल संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उपनल कर्मियों की वर्षों पुरानी लंबित मांग को सीएम धामी ने किया पूरा

पथ प्रवाह, देहरादून। उपनल कर्मियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश जारी हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे, इस बीच कई सरकारें बदली। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। यह उपलल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों लोगों के भविष्य से जुड़ेएक और जटिल विषय का समाधान कर दिया है। जिससे ना सिर्फ विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि उपनल कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे वर्षों पुरानी लंबित मांगों पर ठोस कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं।

डीएम प्रशांत आर्य ने डुंडा विकास और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर दिया जोर

पथ प्रवाह, डुंडा/उत्तरकाशी

विकासखंड डुंडा में आयोजित क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) की बैठक जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और जनता के बीच समन्वय का सशक्त मंच बनकर उभरी। बैठक में क्षेत्रीय विकास एवं जनसमस्याओं के समाधान को लेकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रचनात्मक चर्चा हुई। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि बीडीसी बैठक जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सदन में उठाए गए मामलों पर अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। बैठक ब्लॉक प्रमुख डुंडा राजदीप परमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपजिलाधिकारी डुंडा देवानंद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय

अधिकारियों ने भाग लिया।

शिकायतों पर बनी संयुक्त टीमें

ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार ने कहा कि बीडीसी बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों–सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य–पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया और उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

बैठक में ग्राम प्रधान पनोथ एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य कल्याणी द्वारा सोलर प्लांट एवं विद्युत लाइन शिफ्ट करने की मांग उठाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी, लोनिवि, यूपीसीएल और संबंधित जनप्रतिनिधियों की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए। बड़ेथी-खरवा-कव्वाँ मार्ग की खराब स्थिति

पर अधिशासी अभियंता लोनिवि ने तत्काल जेसीबी भेजकर मार्ग सुधार का भरोसा दिलाया।

ग्राम प्रधान वीरपुर डुंडा द्वारा कूड़ा निस्तारण की समस्या उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने डंपिंग जोन हेतु उपयुक्त स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़ेथ द्वारा क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर की शिकायत पर ब्लॉक प्रमुख ने तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान जुणगा द्वारा इंटर कॉलेज में लघु सिंचाई विभाग द्वारा किए गए लगभग ?9.47 लाख के कार्य की जांच की मांग पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा।

बैठक में विद्युत व्यवस्था, नए संयोजन, खुले तार, झुके पोल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि, उद्यान, पर्यटन, समाज कल्याण, पशुपालन, युवा कल्याण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने सदन में व्यवस्थित और सकारात्मक चर्चा तथा समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रशासन का आभार जताया। बैठक में ज्येष्ठ उप प्रमुख सरिता देवी, कनिष्ठ उप प्रमुख गोपाल अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य हीरा लाल शाह, मदन बिजल्वाण, प्रियंका रावत, भरत सिंह बिष्ट, समस्त ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अनेक जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

गुमशुदा किशोर को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। कोतवाली धरासू क्षेत्र से लापता किशोर को कोतवाली धरासू और

आपरेशन इस्माइल की टीम ने सकुशल ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया। बेटे को सामने पाकर परिजनों के उदास चेहरों पर खुशी लौट आयी। पुलिस के मुताबिक बीती 27 जनवरी को महिला द्वारा कोतवाली धरासू पर आकर अपने 16 वर्षीय पुत्र के घर से बिना बताये कहीं चले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी, तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा कोतवाली धरासू पर किशोर की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। मामले की गम्भीरता को देखते पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा गुमशुदा की तलाश के लिए कोतवाली धरासू व ऑपरेशन स्माइल की टीम को जरुरी निर्देश दिये गये। पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक धरासू मनोज असवाल के नेतृत्व में ऑपरेशन स्माइल व धरासू पुलिस की टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी व तकनीकी माध्यम से जानकारी जुटाते हुये बीती 2 फरवरी को गुमशुदा किशोर को उत्तरकाशी क्षेत्र से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

सिलाई सेंटर से हुनर को मिला नया आयाम, रीप परियोजना से मिला रोजगार को संबल

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड लमगड़ा अंतर्गत ग्राम कपकोट निवासी मंजू कपकोटी ने रीप परियोजना के सहयोग से अपने सिलाई व्यवसाय को नया विस्तार देकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। मंजू कपकोटी वर्ष 2018 से कफकोट की प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तथा वर्तमान में स्वागत सहकारिता के अंतर्गत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे पिछले 8 वर्षों से सिलाई का कार्य कर रही हैं। मंजू कपकोटी के अनुसार क्षेत्र में सिलाई की दुकानों की संख्या बढ़ने और रेडीमेड कपड़ों की उपलब्धता के कारण ग्राहकों की संख्या कम होने लगी थी, जिससे व्यवसाय को आगे बढ़ाना और स्थायी आय सुनिश्चित करना चुनौती बन गया था। इस स्थिति में रीप परियोजना के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण एवं व्यवसाय विस्तार के लिए सहयोग प्रदान किया गया। उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लगभग 3 लाख रुपये की व्यावसायिक योजना तैयार की गई, जिसमें 75 हजार रुपये परियोजना सहायता, 1 लाख 50 हजार रुपये बैंक ऋण तथा 85 हजार रुपये स्वयं का अंशदान शामिल रहा। रीप के जिला परियोजना प्रबंधक राजेश मठपाल ने बताया कि इस वित्तीय सहयोग से मंजू कपकोटी ने अपने सिलाई केंद्र के लिए आवश्यक मशीनें एवं उपकरण उपलब्ध कराए, जिनमें दो पायदान सहित हाथ की मशीन, पिको मशीन, इंटरलॉक मशीन तथा काउंटर टेबल आदि शामिल हैं।

कार्यशाला में उत्साह और ऊर्जा का वातावरण, छात्र–छात्राएं सीख रहे आत्मरक्षा के गुर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित साप्ताहिक आत्मरक्षा कार्यशाला के दूसरे दिन मंगलवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत सफल एवं उत्साहपूर्ण रहा। कार्यशाला में छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता और प्रशिक्षण के प्रति बढ़ता उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के अनुभवी प्रशिक्षक रविशंकर राय के कुशल मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक ने सरल, वैज्ञानिक एवं प्रभावी तरीकों से आत्मरक्षा के गुर सिखाते हुए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, साहस और सजगता का विकास किया। कार्यशाला के दौरान छात्र-छात्राओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ-साथ मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और टीम भावना का अभ्यास कराया गया। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक योगदान हो

रहा है। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में विशेष रुचि दिखाते हुए प्रत्येक अभ्यास को पूरे मनोयोग से किया। महिला प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी डॉ श्वेता अवस्थी ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएँ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनमें नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रकोष्ठ की सचिव मीनाक्षी सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला में छात्र-छात्राओं का उत्साह और ऊर्जा यह दर्शाती है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर है। कार्यक्रम में प्रो विंदुमती द्विवेदी, पर्यावरणविद डॉ विनय सेठी, अनिता कुकरेती उपस्थित रहे।

फुटबॉल प्रतियोगिता में 12वीं गढ़वाल की दमदार जीत, फाइनल में बनाई जगह

पथ प्रवाह, पाबौ।

पाबौ के खूंडेश्वर खेल मैदान में आयोजित स्वर्गीय विपिन सिंह एवं स्वर्गीय प्रताप सिंह राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए रोमांच से भरपूर रहे। तेज रफ्तार खेल, अनुशासित रणनीति और खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने मैदान को खेल प्रेमियों के उत्साह से भर दिया। मंगलवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 12वीं गढ़वाल राइफल्स और कंडोलिया एफसी पौड़ी आमने-सामने रहीं। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन 9वें मिनट में 12वीं गढ़वाल राइफल्स के अभिषेक ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद कंडोलिया एफसी ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, पर 12वीं गढ़वाल की मजबूत रक्षा पंक्ति ने हर हमले को नाकाम कर दिया। अंततः 12वीं

गढ़वाल राइफल्स ने 1-0 से मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पाबौ सुरेंद्र सिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि गुलाब सिंह बिष्ट, पाबौ चौकी इंचार्ज मुकेश गैरोला सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में देव सिंह नेगी, सरतपाल चौधरी, धर्म सिंह नेगी, ज्योत सिंह, डॉ. हंसराज, मनदीप चौहान, पद्मेंद्र सिंह गुसाईं, डॉ. नरेंद्र सिंह रावत, दिनेश सिंह रावत, ग्राम कोटली के जयपाल सिंह सहित अनेक खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच में निर्णायक की भूमिका सुदर्शन नेगी, टिंकू और हुक्कम सिंह रावत ने निभाई, जबकि मेडिकल टीम में प्रदीप सिंह रावत व प्रदीप सिंह नेगी तैनात रहे। कमेंट्री मातवर सिंह चौहान, सचिन रावत व सुधीर रावत ने की। पूरे मुकाबले का फेसबुक लाइव प्रसारण हरेंद्र कोहली द्वारा किया गया।

ऋषिकेश स्नेचिंग कांड का खुलासा, नशे के लिए कुंडल छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, ऋषिकेश।

दून पुलिस ने ऋषिकेश क्षेत्र में हुई स्नेचिंग की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से महिला से छीने गए कुंडल बरामद कर लिए हैं, जबकि घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी सीज किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभियुक्त नशे का आदी है और नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले के अनुसार, वादिनी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री त्रिलोक सिंह, निवासी गुमानीवाला ऋषिकेश ने कोतवाली

ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया कि 1 फरवरी 2026 की सुबह भट्टोवाला रोड स्थित डिवाइन ग्लोबल स्कूल के पास एक अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्ति उनके कान के कुंडल छीनकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0 51/2026 धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल व आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। लगातार सुरागरसी-पतारसी के बाद 2 फरवरी 2026 को मंशा देवी फाटक के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त आकाश पुत्र नरेश कुमार, निवासी ग्राम सिरडी सेडा, थाना धामपुर, जिला बिजनौर (उ0प्र0), हाल पता बाल्मीकि खाड़ा, श्रोत मुनि की रेती, जिला टिहरी गढ़वाल, उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

जनता की समस्याओं पर प्रशासन संवेदनशील, श्रीनगर तहसील दिवस में हुआ समाधान

पथ प्रवाह, पौड़ी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से मंगलवार को श्रीनगर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने की। इस दौरान आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित विभागों द्वारा मौके पर ही अथवा शीघ्र समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।

जिलाधिकारी ने बताया कि सेमला गांव में पेयजल समस्या से संबंधित शिकायत पर जल निगम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा तथा तकनीकी समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। वहीं नकोट गांव में जल भंडारण टैंक की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। देहलचौरी रोड पर क्षतिग्रस्त पुश्ते एवं स्कपर से जुड़ी शिकायत पर उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत एवं सुधार कार्य की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीनगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा फेंके जाने की शिकायत पर नगर निगम द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाए जाने तथा दोषियों की पहचान कर चालानी कार्रवाई

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आवश्यकता वाले स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पार्षदों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीवर लाइन का पानी सड़कों पर बहने की शिकायत पर नगर निगम द्वारा सुधारात्मक कार्य शुरू किए जाएंगे तथा निर्माण सामग्री एवं मलबा सड़कों पर रखे जाने की शिकायत पर पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी।

धारीदेवी क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था पर फोकस

धारी देवी पहुंच मार्ग पर सुरक्षा कार्यों को लेकर प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही धारी देवी क्षेत्र में जाम की समस्या के समाधान हेतु वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धारी देवी क्षेत्र में स्थायी पार्किंग का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित है। साथ ही क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्य प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करना, लाइटिंग तथा रोड साइनेज से संबंधित कार्य शामिल हैं।

अतिक्रमण की शिकायत पर जांच के आदेश

जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर उपजिलाधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही रेलवे से क्षतिग्रस्त भवनों में जल बिल आने की शिकायत पर जल संस्थान द्वारा परीक्षण कर आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने नालियों के अंडरग्राउंड निर्माण से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर आख्या तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

समय से किया जाए समस्याओं का निस्तारण

जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर स्थलीय निरीक्षण के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है, जिससे समस्याओं का स्थायी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने निस्तारण की जानकारी समयबद्ध रूप से संकलित कर आवेदकों को अवगत कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि छोटी-छोटी आवश्यकताओं को जिला योजना में सम्मिलित कर कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाय। अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल ने बताया कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है, जिनमें अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई जारी है और प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है।

ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, अधिशासी अभियंता एनएच राजीव चौहान, जिला बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई मुकेश दत्त, जिला शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह नेगी, सहायक निबंधक सहकारिता सौरभ कुमार, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मनेरा स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण ले रही छात्राओं से की वार्ता

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने खेल छात्रावास में रह रही छात्राओं से बातचीत करते हुए उनके दैनिक जीवन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पढ़ाई से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्राओं से खुले मन से अपनी समस्याएँ, सुझाव और अनुभव साझा करने को कहा तथा भरोसा दिलाया कि उनकी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं को नियमित अभ्यास, अनुशासन और

समय प्रबंधन के महत्व के बारे में समझाया तथा कहा कि खेल के साथ-साथ शिक्षा भी

उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि खेल छात्रावास का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्राओं को बेहतर वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार करना है। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास बनाए रखने, कठिन परिश्रम करने और किसी भी समस्या की स्थिति में छात्रावास प्रशासन या जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क करने का मार्गदर्शन दिया। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी बबीता बिष्ट भी उपस्थित रही।

एक नजर

रोड कटिंग में लापरवाही : एक्सईएन व ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, देहरादून। शहर में रोड कटिंग के दौरान नियमों की अनदेखी और जनसुरक्षा से खिलवाड़ करना पिटकुल के अधिकारियों और ठेकेदार को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग की अनुमति निरस्त कर दी है और कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता एवं ठेकेदार के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मौके पर प्रयुक्त मशीनरी भी जब्त कर ली गई है। एलआईसी बिल्डिंग के समीप विद्युत केबल को भूमिगत करने के कार्य के दौरान लगातार हो रही लापरवाही के कारण आमजन के घायल होने की घटनाओं को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया कि शहर में यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि पिटकुल की संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। कार्य निर्धारित समय के विपरीत किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आमजन को भारी असुविधा व सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

गौरतलब है कि 135 केवी आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 केवी माजरा-लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने के लिए कुल 1996 मीटर लंबाई में रोड कटिंग (5 रोड क्रॉसिंग सहित) की सशर्त अनुमति 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक, रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक दी गई थी। लेकिन निरीक्षण में शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर जिला प्रशासन ने अग्रिम आदेशों तक कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए अनुमति रद्द कर दी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर पिटकुल को सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, ठेकेदारों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।

पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से न रहे वंचित: सीडीओ

पथ प्रवाह, पौड़ी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत मंगलवार को विकासखंड बीरोंखाल की न्याय पंचायत कोटा में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 29 शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। 114 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में 657 लोगों ने प्रतिभाग किया।

शिविर की अध्यक्षता सीडीओ गिरीश गुणवंत ने की। उन्होंने लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। शिविर के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। कई शिकायतों का समाधान उन्होंने मौके पर ही कराते हुए अधिकारियों को

संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा। सीडीओ ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से ग्रामीणों को शासन-प्रशासन से सीधे जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजन को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख नेहा नेगी, ज्येष्ठ उप प्रमुख कुलदीप सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी थलीसैंण कृष्णा त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी सुदर्शन सिंह बुटोला, नोडल अधिकारी शिविर एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली संदीप तोमर, सहायक विकास अधिकारी पंचायत राजेंद्र सिंह रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

देहरादून जिला प्रशासन ने विधवा शांति राणा को दिया जीवन का संबल

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कठिन परिस्थितियों से जूझ रही विधवा शांति राणा को बड़ा सहारा प्रदान किया है। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी, बैंक ऋण और तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी से दबे परिवार को राहत देते हुए जिला प्रशासन ने सीएसआर फंड के माध्यम से शांति राणा के बैंक खाते में 4 लाख रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की है। इस सहायता से उनके पति द्वारा ई-रिक्शा क्रय हेतु लिया गया बैंक ऋण पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, जिससे उनके सिर से कर्ज का भारी बोझ उतर गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने शांति राणा की 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पुत्री अंशिका की शिक्षा को सुरक्षित करते हुए कक्षा 12वीं तक की एकमुश्त 1.62 लाख रुपये की फीस सीधे संबंधित स्कूल प्रबंधन के खाते में जमा कराई है। इस निर्णय से न केवल शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित हुई है, बल्कि पीड़ित मां और बच्चों को भविष्य की बड़ी चिंता से भी मुक्त कर दिया गया है।

शिक्षा से रोजगार तक प्रशासन की बहुआयामी मदद

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में विगत नवंबर माह में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शांति राणा ने अपनी व्यथा साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पति मनबहादुर ने परिवार की आजीविका के लिए ई-रिक्शा खरीदने हेतु 3,72,600 रुपये का बैंक ऋण लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार में कोई कमाने वाला शेष नहीं रहा। वर्तमान में शांति राणा अपनी 12 वर्षीय पुत्री अंशिका, 5 वर्षीय पुत्र अक्षय तथा एक अन्य किशोर पुत्र के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अकेले निभा रही थीं और सीमित संसाधनों के कारण बैंक की किश्तें जमा कर पाने में असमर्थ थीं।

डीजीपी दीपम सेठ का सख्त निर्देश: अपराध, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ ने की। सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गढ़वाल एवं कुमाऊँ परिक्षेत्र के रेंज प्रभारी, सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ के अधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रदेश में वर्तमान अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था, गंभीर आपराधिक घटनाओं की विवेचना, लंबित मामलों और जनशिकायतों के निस्तारण की गहन समीक्षा की गई। डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनावश्यक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाल ही में ऋषिकेश क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर एम्स चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक साहिल वशिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसी प्रकार कोतवाली नगर देहरादून में युवती के जघन्य हत्याकांड में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक प्रद्युम्न नेगी को भी निलंबित किया गया। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों मामलों की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम श्रीमती विशाखा अशोक भदाणे को सौंपी गई है। अन्य पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच कर 07 दिवस में विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में हरिद्वार जनपद के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविदास जयंती के दौरान दो पक्षों में हुए संघर्ष एवं गोलीबारी की घटना में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर चुड़ियाला हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक सूरत शर्मा को निलंबित किया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक क्राइम हरिद्वार श्री जितेन्द्र मेहरा को सौंपी गई है।

भूमि धोखाधड़ी यानी लैंड फ्रॉड के मामलों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि अब ऐसे सभी मामलों में क्षेत्राधिकारी (सीओ) स्तर पर समयबद्ध और पारदर्शी प्रारंभिक जांच अनिवार्य होगी। जांच में स्पष्ट किया जाएगा कि मामला सिविल है या आपराधिक, उसके बाद ही आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लंबित भूमि संबंधी मामलों की लगातार मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर से की जाएगी।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए डीजीपी दीपम सेठ ने सतर्कता विभाग को निर्देशित किया कि भ्रष्ट आचरण में लिप्त पुलिस कर्मियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

बैठक में महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा अभिनव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विजिलेंस एवं अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन ए.पी. अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक पी/एम विम्मी सचदेवा, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊँ परिक्षेत्र रिधिम अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार कृष्ण कुमार वी.के., पुलिस महानिरीक्षक साइबर नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा करन सिंह नगन्याल, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र सदानन्द दाते, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक योगेन्द्र रावत, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था धीरेन्द्र गुंज्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 2027 की तैयारियों का शुभारंभ, 11 अखाड़ों का भूमि पूजन

पथ प्रवाह, नासिक/त्र्यंबकेश्वर।

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ (कुंभ मेला 2027) की तैयारियों का आज विधिवत शुभारंभ हो गया। पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्रीं आवाहन अखाड़ा, श्रीं अग्नि अखाड़ा, श्रीं निरंजनी अखाड़ा, श्रीं आनंद अखाड़ा, श्रीं महानिर्माणी अखाड़ा, श्रीं अटल अखाड़ा, श्रीं बड़ा अखाड़ा उदासी, श्रीं नया अखाड़ा उदासी, श्रीं निर्मल अखाड़ा सहित कुल 11 अखाड़ों द्वारा त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर साधु-संतों और अखाड़ा प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन 31 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होकर जुलाई 2028 तक चलेगा, जबकि मुख्य आयोजन वर्ष 2027 में होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 24 जुलाई 2027 को

ध्वजारोहण के साथ कुंभ मेले की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस सिंहस्थ का प्रमुख आकर्षण शाही स्नान होंगे, जिनमें पहला शाही स्नान सोमवती अमावस्या के अवसर पर 2 अगस्त 2027 को होगा। दूसरा शाही स्नान 31 अगस्त 2027 तथा तीसरा शाही स्नान 11 सितंबर 2027 (एकादशी) को संपन्न होगा। सभी शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर स्थित कुशावर्त तीर्थ पर आयोजित किए जाएंगे। लगभग 21 महीनों तक चलने वाला यह कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। विशेष बात यह है कि सिंहस्थ कुंभ 2027 को 'प्रौद्योगिकी-सक्षम कुंभ' के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश के पावन संयोग में आयोजित इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु और साधु-संत गोदावरी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे।

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, रोजगार प्रयाग पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों और विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिये इच्छुक अभ्यर्थियों को कौशल विकास विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग के विभिन्न कार्यालयों व विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 रिक्त पदों (मृत संवर्ग) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की आधिकारिक बेवसाइट रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन मांगे गये हैं। जिसकी अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती आउटससोर्स के माध्यम से की जायेगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी की जनदवार रिक्तयां प्रकाशित कर दी है। जिसमें उत्तरकाशी जनपद में 135 पदों पर आवेदन मांगे गये हैं। इसी प्रकार रूद्रप्रयाग में 106, टिहरी 268, ऊधमसिंह नगर 182, पिथौरागढ़ 197, पौड़ी 340, बागेश्वर 89, अल्मोड़ा 254, चमोली 179, चम्पावत 120, देहरादून 195, हरिद्वार 91 तथा नैनीताल में 208 पदों पर भर्ती की

जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक/प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक व बेसिक कार्यालय सहित इंटर कॉलेज व हाईस्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती दी जायेगी। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को प्रत्येक माह 15,000 रूपये मानदेय दिया जायेगा।

विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धनसिंह रावत का कहना है कि शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों में तैनाती दी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिये गये हैं।

हिन्दू-सनातन है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म: संजय

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरिद्वार नगर के तत्वावधान में मायापुरी बस्ती क्षेत्र का विराट हिन्दू सम्मेलन सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर के प्रांगण में मायापुर हिन्दू सम्मेलन आयोजन समिति द्वारा आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि गरीब दासीय आश्रम के संचालक भगवताचार्य स्वामी रविदेव शास्त्री ने सनातन धर्म की विशेषताएं बताते हुए हर व्यक्ति से अपनी परम्पराओं का पालन करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त प्रचार प्रमुख संजय जी ने हिन्दू धर्म की प्राचीनता, गौरव, और उसकी गरिमामयी उपलब्धयों का वर्णन करते हुए हर नागरिक से अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ राष्ट्र धर्म का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सबसे प्राचीन सनातन हिदू धर्म, परंपराएं है। विश्व के अन्य सभी धर्म सनातन से ही निकले है। भारत की धरती पर सिख,जैन, बौद्ध सहित सैकड़ों पथ सम्प्रदाय हैं, जिनका उद्देश्य विश्व में शांति व सबका कल्याण करना ही है। सनातन धर्म जोड़ने का भाव रखता है। प्रान्त प्रचार प्रमुख संजय जी

ने संघ के शताब्दी वर्ष पर लिए गए पंच परिवर्तन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, स्वःबोध, कुटुंब प्रबोधन तथा समाजिक समरसता पर बल दिया। सम्मेलन को विशिष्ट अतिथि साध्वी महंत गंगा दास जी ने भी सम्बोधित किया। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वालित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। अंत में कार्यक्रम के संरक्षक महंत विष्णु दास ने सभी का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन का सफल संचालन चंद्र शेखर कुर्ल ने किया। आयोजन समिति के संयोजक मुकेश जोशी, सहसंयोजक मनोज मंत्री, कोषाध्यक्ष समाजसेवी राकेश गोयल, एवं शिक्षा विद विजय पाल सिंह जी एवं करुणेश सैनी जी तथा वरिष्ठ भाजपा नेता प्रांतीय सहमडिया संयोजक विकास तिवारी, मनोज मंत्री का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। सभा में पूर्व मेयर मनोज गर्ग, समाजसेवी जगदीश लाल पाहवा, दीपक शर्मा पार्षद, सचिन कुमार पार्षद मंजू रावत पार्षद, अपने साथियों के साथ सम्लित हुए। इसके बड़ी संख्या में क्षेत्र में संचालित संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का सख्त एक्शन, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

थाना भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बिनारसी में रविदास जयंती के उपरांत हुए विवाद में दो व्यक्तियों की मृत्यु के मामले को एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। मामले में लापरवाही सामने आने पर चौकी प्रभारी तेज्जुपुर समेत एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शेखर सुयाल द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि संबंधित पुलिसकर्मी घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय से मौके पर नहीं पहुंचे और न ही उच्चाधिकारियों को समय पर घटना की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस की निष्क्रियता के चलते स्थिति को नियंत्रित करने में विलंब हुआ, जिसके गंभीर परिणाम सामने आए।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com